

Session : 7

Date : 02-03-2006

Participants : Varma Shri Ratilal Kalidas

>

Title : Regarding the need to grant clearance to ‘Control of Organised Crime in Gujarat’ Bill sent by the Government of Gujarat.

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा (धन्धुका) : महोदय, गुजरात संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक सन 2003 में गुजरात विधान सभा में पारित कर तत्कालीन माननीय राज्यपाल महोदय की ओर से स्वीकृति हेतु महामहिम राष्ट्रपति जी के पास भेजा गया है।

चूंकि उल्लेखित विधेयक में केन्द्रीय गृह मंत्रालय द्वारा धारा 14 से 16 तक को रद्द करने की संस्तुति की गयी थी। जिसे मान्य कर प्रदेश सरकार ने संशोधित विधेयक को नियम सार विधान सभा में पारित किया तथा सन 2004 जून में महामहिम राष्ट्रपति जी को स्वीकृति हेतु भेजा। यह विधेयक भी महाराष्ट्र सरकार द्वारा लागू किये गये विधेयक की तर्ज पर ही है, जिसमें गिरोह बंद अपराधियों की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने हेतु प्रदेश पुलिस को विशेष अधिकार प्रदान करने का प्रावधान हो।

गुजरात सामुद्रिक सीमा क्षेत्र प्रदेश होने के साथ साथ मुम्बई के भी निकट है तथा महाराष्ट्र से खदेड़े गये गिरोह गुजरात में घुसकर अपनी गतिविधियां चलाने लगे हैं, जिसे नियंत्रित करने की दृष्टि से उपरोक्त विधेयक को लागू करना प्रदेश की प्रथम आवश्यकता है।

मेरी मांग है कि राज्य में शांति स्थापना व नागरिकों की सुरक्षा की दृष्टि से उल्लेखित विधेयक को अति जल्द स्वीकृति प्रदान की जाये।